

प्रेषक:-

डा० एम०सी० जोशी
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

ऊर्जा विभाग,

देहरादून: दिनांक: २९, सितम्बर, 2004

विषय:- वित्तीय वर्ष 2004-05 में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० को ग्रामीण विद्युतीकरण के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर नोडल ऐजेन्सी तथा जनपद एवं विकासखण्ड स्तर पर समितियाँ गठित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या 554/वि०अनु०-1/2004, दिनांक 30.07.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वर्ष 2007 तक ग्रामों तथा वर्ष 2009 तक सभी परिवारों के विद्युतीकरण किये जाने के लक्ष्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण की बदली हुई परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में तथा सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाओं का विकासखण्डवार/जनपद पर सूचनाओं का संकलन करने हेतु अनुदान के रूप में रु० 18 लाख (रु० अठ्ठाईस लाख मात्र) की धनराशि संलग्नक में वर्णित जनपदवार फॉट के अनुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- स्वीकृत धनराशि के बिल उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा तैयार/हस्ताक्षरित किये जायेंगे तथा सम्बन्धित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार से धनराशि का आहरण किया जायेगा।
- 2- प्रत्येक अनुदान आहरण की सूचना महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, निधि लेखाशीर्षक सूचित करते हुये भेजेंगे।
- 3- स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन को दिनांक 31.03.2005 तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा।
- 4- स्वीकृत धनराशि का कार्यवार विस्तृत फॉट का विवरण एक माह के अन्दर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा व्यय/कार्य पूर्ण करने के उपरान्त भी कार्यवार व्यय की फॉट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 5- आवंटित धनराशि को किसी ऐसी मद जिसके लिये फाइनेन्सियल हैण्ड बुक, बजट मैनुअल तथा स्टोर चार्ज के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो तदनुसार स्वीकृति प्राप्त करके व्यय किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय।
- 7- जनपदवार व्यय आवंटित सीमा तक ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी स्थिति में आवंटन से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा, अन्यथा इसका वित्त पोषण शासन द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व जिन कार्यों हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किया जायेगा, इस विषय में दिशा निर्देश/फॉट तयकर उसका विवरण जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

C

.....2

9- स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801-विजली-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-ग्रामीण विद्युतीकरण का नियोजन तथा अनुश्रवण-00-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1373/वि0अनु0-3/04, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय


/
(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 511/1/2004-05/02/04, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 2- अपर निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 4- समस्त कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-3।
- 6- सचिव, नियोजन विभाग।
- 7- सचिव, विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
- 8- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०, देहरादून।
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,


(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 511 /1/2004-05/02/04, दिनांक: 29 सितम्बर, 2004 का संलग्नक

(पुनरांशित) (हजार रुपये में)

क्रमांक	मद	जनपद	धनराशि
1	2	3	4
	जिला सेक्टर:-		
1-	ग्रामीण विद्युतीकरण के नियोजन एवं अनुश्रवण कार्यो हेतु नीति बनाया जाना।	नैनीताल उधमसिंह नगर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर धम्पावत देहरादून पौड़ी टिहरी चमोली उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग हरिद्वार	130 100 130 200 100 100 130 350 130 130 100 100 100
		योग:-	1800

कुल योग रु0 18,00,000.00 (रु0 अठ्ठारह लाख मात्र)

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव